Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.gisrrj.com
OPEN ACCESS
© 2025 GISRRJ | Volume 8 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय असमानताएँ और सामाजिक-आर्थिक विकास: विकास प्रतिरूपों और नीतिगत हस्तक्षेपों का भौगोलिक विश्लेषण

Kavita Yadav
Research Scholar , Department of Geography
Prof. Upma Chaturvedi
Avadh Girl's Degree College Lucknow, India

Article Info
Volume 8, Issue 2

Page Number : 10-21

Publication Issue :
March-April-2025

Article History
Accepted : 01 March 2025
Published : 05 March 2025

सार: अध्ययन में सामाजिक-आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं के पैटर्न का आकलन किया गया है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक असमानताओं की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए, कृषि, औद्योगिक और बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों के लिए विकास के स्तर का अलग-अलग आकलन किया जाता है और जिलों को निर्मित विकास सूचकांक के मूल्यों के अनुसार चार विकास श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक समान क्षेत्रीय विकास लाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, वंचित जिलों के लिए मॉडल जिलों की पहचान की गई है और विभिन्न सामाजिक सुविधाओं के लिए संभावित लक्ष्यों का अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास के स्तर की तुलना करने का भी प्रयास किया गया है। परिणाम दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के भीतर और उनके बीच विभिन्न जिलों में सामाजिक-आर्थिक विकास के स्तर में व्यापक असमानताएँ मौजूद हैं। अवसंरचना सेवा क्षेत्र में विकास का स्तर समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ पाया गया है, जो दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में इन क्षेत्रों की वृद्धि और प्रगति साथ-साथ चल रही है। परिणाम दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का स्तर कृषि और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता है, जबकि कृषि विकास समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। अध्ययन से पता चलता है कि कम विकसित जिलों को अपने समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए अधिकांश संकेतकों में सुधार की आवश्यकता है।

शब्दावली: क्षेत्रीय असमानताएँ, सामाजिक आर्थिक विकास, विकास प्रतिरूप और भौगोलिक विश्लेषण आदि।

Copyright © 2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution **4.0 International License (CC BY-NC 4.0)**

प्रस्तावना:

सामाजिक-आर्थिक विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है। इसके लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों की संतुष्टि, विकास लाभों और अवसरों का समान वितरण, सम्मानजनक रहने का माहौल, लैंगिक समानता और गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों का सशक्तिकरण, यानी "संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का ऊपर की ओर बढ़ना" की आवश्यकता होती है, जैसा कि गुन्नार मिर्डल (1972) ने अपने अग्रणी कार्य "द एशियन ड्रामा: एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस" में परिभाषित किया है। ब्लैक (1966) ने विकास को कई आदर्शों की प्राप्ति के रूप में उचित रूप से परिभाषित किया है जैसे "उत्पादकता में वृद्धि, सामाजिक-आर्थिक समानता, आधुनिक ज्ञान, बेहतर संस्थान और दृष्टिकोण और नीति उपायों की एक तर्कसंगत रूप से समन्वित प्रणाली जो सामाजिक व्यवस्था में अवांछनीय स्थितियों को दूर कर सकती है जिसने अविकसितता की स्थिति को बनाए रखा है"। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यक्रमों को विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करके आम जनता के लिए उच्च जीवन स्तर प्राप्त करना है, साथ ही उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण में सुधार लाना है। उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए विकास कार्यक्रमों का एक प्रमुख उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास लाना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश में आर्थिक नियोजन पारंपरिक रूप से वंचित क्षेत्रों को विशेष सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर केंद्रित रहा है। यद्यपि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ), सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी), वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आईएपी), भारत निर्माण, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सब्सिडी और अनुदान जैसे कई उपकरणों के माध्यम से अविकसित क्षेत्रों में संसाधन हस्तांतरण किया जा रहा है, लेकिन पर्याप्त सबूत हैं कि सामाजिक-आर्थिक विकास के संदर्भ में देश के भीतर क्षेत्रीय असमानताएं समय के साथ कम नहीं हो रही हैं, जो आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों के लिए सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार पैदा करती है ।

स्थानिक ध्रुवीकरण का सिद्धांत और 'विकास ध्रुवों' की धारणा, जैसा कि पेरौक्स (1955) द्वारा तैयार किया गया था, का तात्पर्य है कि पूंजीवादी समाजों में बाजार तंत्र के मुक्त कामकाज क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ाते हैं, जिससे अमीर क्षेत्र और अधिक अमीर हो जाते हैं और गरीब क्षेत्र और अधिक गरीब हो जाते हैं। इस तरह विकास का स्थानिक ध्रुवीकरण आर्थिक असमानताओं को जन्म देता है, जो सामाजिक असमानताओं के साथ होती हैं। ये सामाजिक तनावों और संघर्षों और राजनीतिक अस्थिरता के लिए एक स्पर्श-पत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्थानिक ध्रुवीकरण के सिद्धांत ने भारतीय संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। अब यह सर्वविदित है कि भारत ने खुद को एक निम्न-आय वाले विकासशील देश से मध्यम-आय वाले विकासशील देश में बदल लिया है, लेकिन लगातार बहिष्कृत समूह इसके आर्थिक विकास के प्रक्षेपवक्र से बाहर हैं। जैसा कि भारत सरकार (गोल) ने आर्थिक सर्वेक्षण (2012) में देखा है कि विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाने में, चुनौती क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को यथासंभव प्रभावी और टिकाऊ तरीके से पाटने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करना है। सूक्ष्म स्तर पर क्षेत्रीय असमानताओं की पहचान और क्षेत्रीय विकास पैटर्न को मापना नीति निर्माण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। योजना आयोग (2011) द्वारा भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के दृष्टिकोण पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है, जिसका शीर्षक है: "तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास" और इसके अध्याय 11: 'सामाजिक और क्षेत्रीय समानता' में विस्तार से

बताया गया है कि शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों के साथ भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास से आजीविका और आय में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप कम विकसित क्षेत्रों के साथ आर्थिक विकास के लाभों को बेहतर तरीके से साझा किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में आर्थिक नियोजन में जिस समावेशी विकास की परिकल्पना की गई है, उसमें अंतर-राज्यीय, अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-अनुभागीय असमानताओं को कम करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य शामिल है। समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास पर राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जानकारी प्रभावी मानवीय प्रयासों के लिए पर्याप्त सुराग नहीं देती है क्योंकि भारत में, क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं और संसाधन संपदा के संबंध में भिन्न हैं । भारतीय संदर्भ में, वानमाली और इस्लाम द्वारा यह सही तर्क दिया गया है कि जिला स्तर पर एक अध्ययन जिला विशिष्ट विकास नीतियों को तैयार करने के लिए अधिक उपयोगी होगा। चूंकि जिला-स्तरीय आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण की आवश्यकता के बारे में आम सहमति बढ़ रही है, इसलिए जिला स्तर पर सामाजिक-आर्थिक विकास के स्तर को मापना दिलचस्प होगा।

उत्तर प्रदेश के चयनित क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास :

यह ध्यान में रखते हुए कि किसी विशेष क्षेत्र के उपलब्ध संसाधनों का विस्तृत विश्लेषण और विकास दक्षता के अपेक्षित स्तरों के बारे में निष्कर्षों का एक सेट सफल क्षेत्रीय विकास नियोजन के अपरिहार्य साधन हैं, अब हम अध्ययन के लिए चुने गए उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास प्रोफाइल की संक्षिप्त समीक्षा करते हैं। ये हैं: उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, और दक्षिणी क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं। इन क्षेत्रों का चयन उनके स्थान के आधार पर और जिला स्तर पर डेटा उपलब्धता की बाधाओं को पूरा करके किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि प्रधान है। 'हरित क्रांति' के आगमन और औद्योगिक मोर्चे की सराहनीय प्रगति ने निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र और विनिर्मित वस्तुओं में राज्य के कुल उत्पादन में वृद्धि की है, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ये उपलब्धियाँ विभिन्न जिलों के बीच सामाजिक-आर्थिक विकास में असमानताओं के स्तर को काफी हद तक कम करने में सक्षम रही हैं। यदि आबादी के बड़े हिस्से को पीछे छोड़ दिया जाता है, भले ही केवल सापेक्ष रूप से, तो राज्य में सतत विकास की व्यवहार्यता को खतरा हो सकता है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है और यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा व क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 09 राज्यों से लगी है, राज्य के उत्तर में उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा दिल्ली तथा राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार तथा झारखण्ड राज्य स्थित हैं। इनके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर तथा दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है तथा सर्वाधिक सीमा की लम्बाई भी मध्य प्रदेश के साथ है। उत्तर प्रदेश का अंक्षाशीय विस्तार 23° 52° उत्तरी अक्षांश से 30°24' उत्तरी अक्षांश तक तथा 77°05' पूर्वी देशान्तर से 84°38' पूर्वी देशान्तर तक है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लम्बाई 650 कि०मी० तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई 240 कि०मी० है। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से उत्तर में मिलती है। नेपाल की सीमा से उत्तर प्रदेश के 07 जिले जुड़े हैं, जो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत

हैं। प्रदेश की नेपाल सीमा से लम्बाई लगभग 579 कि०मी० है। इन जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए भारत साकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना "बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम" संचालित है।

पर्यटन व उद्योग:

पर्यटन एक ऐसा सरल माध्यम है जिसके द्वारा विशेषकर विदेशी मुद्रा का आसानी से अर्जन होता है। पूर्वाञ्चल के कई स्थल पर्यटन व उद्योग के लिए विख्यात हैं। पूर्वाञ्चल का वाराणसी जनपद विभिन्न उद्योगों का केन्द्र है, जिसमें बनारसी रेशमी साड़ी, कपड़ा उद्योग, कालीन उद्योग प्रमुख हैं। काशी विश्वनाथ मन्दिर, दशाश्वमेघ घाट एवं अन्य घाट, सारनाथ, ए.एस.आई उत्खनित क्षेत्र एवं घमेख स्तूप वाराणसी के मुख्य पर्यटन स्थल हैं। विन्ध्याचल मण्डल (मीरजापुर) स्थित विन्ध्याचल धाम भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इसके अतिरिक्त अन्य पर्यटन स्थलों में सीता-कुण्ड, काल भैरव मन्दिर, मोती तालाब, तारकेश्वर महादेव, चुनार का किला प्रमुख हैं, जबकि संत रविदासनगर (भदोही) कालीन निर्माण का एक प्रमुख केन्द्र है। महात्मा बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात है। यहाँ विश्व भर से बौद्ध तीर्थ यात्री भ्रमण के लिये आते हैं। कुशीनगर के निकट पावानगरी भगवान महावीर की जन्मस्थली के कारण जैन धर्मावलम्बियों के आर्कषण का केन्द्र भी कुशीनगर है। प्रयागराज में गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष माघ मास में मेला लगता है तथा महाकुम्भ/ कुम्भ का चक्रानुसार आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। वर्ष 2019 में आयोजित कुम्भ मेले में भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अनेक राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों व देसी-विदेशी अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा पावन स्नान किया गया। वर्ष 2019 का कुम्भ स्वच्छता, सुरक्षा व व्यवस्था के दृष्टिकोण से सम्पूर्ण विश्व में एक जिज्ञासा का विषय रहा, जहाँ इस अवधि में लगभग 24 करोड़ लोगों ने पावन स्नान किया। प्रयागराज में दर्शनीय स्थल आनन्द भवन, कम्पनी बाग, मिण्टो पार्क, खुसरो बाग, बड़े हनुमान मन्दिर आदि हैं। अयोध्या को तीर्थकरों की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल श्री रामजन्म भूमि, मणि पर्वत, कनक भवन, हनुमानगढ़ी आदि हैं।

राज्य में किए गए प्रमुख सामाजिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में शामिल हैं: (1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), और (2) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसके तहत एक वित्तीय वर्ष में सौ दिनों की मजदूरी-रोजगार की गारंटी ग्रामीण परिवार को दी जाती है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। आईएवाई का मुख्य उद्देश्य "गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) ग्रामीण परिवारों को आवास इकाइयों के निर्माण/उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करना है, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) और मुक्त बंधुआ मजदूर श्रेणियों जैसे कमजोर समूहों पर विशेष जोर दिया जाता है"। काम न करने वाले बुज़ुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य ने सामाजिक पेंशन योजनाएँ सफलतापूर्वक चलाई हैं, जो बुज़ुर्गों को बिना किसी पूर्व योगदान या श्रम बल से हटने के नकद हस्तांतरण प्रदान करती हैं। इसके अलावा, विशेष रूप से कमज़ोर समूहों के लिए सामाजिक पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा जाल हैं: विकलांग, विधवा, अंधे, बहरे, विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण कदम हैं - पर्याप्त भोजन और आय तक पहुँच वाला जीवन, बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वच्छ जल और स्वच्छता, और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण बनाया है। उदाहरण के लिए, 2023-2024 के दौरान मनरेगा के तहत रोजगार में अनुसूचित जातियों और महिलाओं की हिस्सेदारी 48.93 और 35.62% है। 2023-2024 के दौरान निर्मित कुल घरों में IAY की हिस्सेदारी 0.66% है।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है और रोजगार तथा आय में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में काफी सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए, 2023-2024 में, राज्य सकल घरेलू उत्पाद (एसजीडीपी) की क्षेत्रीय संरचना थी: कृषि और संबद्ध क्षेत्र (16.3%), उद्योग (29.1%), और सेवा (54.6%) जबकि 2020-21 के

लिए संबंधित आंकड़े क्रमशः 31.9, 30 और 38.1% बताए गए थे। कृषि क्षेत्र अभी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालाँकि, राज्य सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार घट रही है,। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की घटती हिस्सेदारी का अर्थ है कि आय असमानता बढ़ रही है क्योंकि लगभग 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और अधिकांश ग्रामीण गरीब परिवार आय और भोजन के प्राथमिक स्रोत के रूप में खेती पर निर्भर हैं। आय प्रदान करने और भोजन के मानव अधिकार को कायम रखने के द्वारा, खेती राज्य में आय और उत्पादन के अपेक्षाकृत समतावादी वितरण के आधार के रूप में एक लचीला ग्रामीण क्षेत्र स्थापित करती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय 2,310 रुपये और 1,510 रुपये है, जिसमें से भोजन का हिस्सा क्रमशः 43 और 54% है। कुल उपभोक्ता व्यय में ग्रामीण लोगों का भोजन का हिस्सा काफी अधिक है क्योंकि भोजन जीवित रहने की प्राथमिक आवश्यकता है और आबादी के गरीब वर्गों में समग्र व्यय का एक बड़ा हिस्सा लेता है।

उत्तर प्रदेश में दूध सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों में से एक है-यह आबादी के लिए प्रोटीन और विटामिन का प्रमुख स्रोत है। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2021-22 में 586 ग्राम प्रति दिन से बढ़कर 2023-24 में 662 ग्राम प्रति दिन हो गई है। 2021-22में 273 ग्राम प्रति दिन के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले उत्तर प्रदेश देश में अग्रणीय है। इसी अवधि के लिए प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन 624 किलोग्राम प्रति वर्ष होने का अनुमान है। मूल्य स्थिरता और विशेष रूप से गरीबों को आसानी से वहनीय मूल्य पर खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चालू किया है। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश का 87% भूमि क्षेत्र कृषि योग्य है जिसमें से 81% सिंचित है। 2023-24 में लगभग 79% कृषि योग्य क्षेत्र को एक बार से अधिक दिखाया गया है। राज्य का क्रॉस क्रॉप्ड क्षेत्र 6,351 हजार हेक्टेयर (हेक्टेयर) है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का प्रतिशत 3.53 है। राज्य में प्रति कृषि श्रमिक कृषि योग्य भूमि लगभग 1.38 हेक्टेयर है जो कि 1.12 हेक्टेयर के अखिल भारतीय स्तर से अधिक है। राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं: गेहूं, चावल, बाजरा, कपास, गन्ना और सरसों। गेहूं और चावल की फसलें अधिक बहुमुखी हैं। गेहूं (4,390 किग्रा/हेक्टेयर) और चावल (3008 किग्रा/हेक्टेयर) की पैदावार 2008-2009 में गेहूं (2,907 किग्रा/हेक्टेयर) और चावल (2,125 किग्रा/हेक्टेयर) है। जबकि विनिर्माण क्षेत्र के लिए वृद्धि दर 2.6% दर्ज की गई। इसके अलावा, तेजी से बढ़ रहा सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी भी राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट के लिए जिम्मेदार है।

अच्छे सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों के कुछ गुण:

ड्रेवनोव्स्की (1972) सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को अवलोकनीय और मापनीय घटना के रूप में परिभाषित करता है जिसमें मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि की डिग्री के बारे में जानकारी होती है। साहित्य का एक सर्वेक्षण अच्छे सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों के निम्नलिखित मुख्य गुण प्रदान करता है। सबसे पहले, जैसा कि मैकग्रानाहनन (1972) ने तर्क दिया है कि एक अच्छा संकेतक विकास की प्रक्रिया या घटक के लिए प्रासंगिक होना चाहिए और जितना संभव हो सके विकास के घटक का प्रतिनिधि होना चाहिए जिसे वह प्रतिबिंबित करता है। दूसरे, एक संकेतक इस अर्थ में व्यापक होना चाहिए कि इसे विकास के घटक के अधिक से अधिक पहलुओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए, जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, प्रति श्रमिक फसल उत्पादकता देश की प्रौद्योगिकी और अनुभव के स्तर से प्रभावित होती है और प्रतिबिंबित करती है और यह बदले में कृषि क्षेत्र में कुल आय जैसे कई कारकों को प्रभावित करती है। तीसरा, एक अच्छे सामाजिक-आर्थिक संकेतक में

परिवर्तन की वही दिशा होनी चाहिए जो मापी जा रही प्रक्रिया, हमारे मामले में, सामाजिक-आर्थिक विकास की है। जैसा कि ड्रूनोव्स्की (1972) ने तर्क दिया है कि इन मूल्यों के परिवर्तन की दिशा कल्याण के परिमाण के परिवर्तन की दिशा के अनुरूप होनी चाहिए जिसे मापा जाना चाहिए। तदनुसार, केवल वे चर जो विकास के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हैं, उन्हें संकेतक के रूप में चुना जाना चाहिए। हालाँकि, इवुसी (1976) का तर्क है कि अन्य चर जो विकास से नकारात्मक रूप से संबंधित हैं, उन्हें संकेतक के रूप में चुना जा सकता है, जब तक कि संकेतक आर्थिक विकास के साथ उत्तरोत्तर खराब होता रहे। चौथा, जैसा कि एडेई (1973) और ड्रेवनोव्स्की (1972) ने तर्क दिया है कि सामाजिक-आर्थिक संकेतक को मात्रात्मक होना चाहिए। मात्रात्मक संकेतकों के संबंध में, ड्रेवनोव्स्की ने एक पाँचवीं विशेषता का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि "कल्याण का एक सार्थक माप प्राप्त करने के लिए न केवल संकेतक का संख्यात्मक मूल्य होना आवश्यक है, बल्कि एक संदर्भ बिंदु भी होना चाहिए जिसके विरुद्ध संकेतक के मूल्य का आकलन किया जा सके। उदाहरण के लिए, यदि हम यह नहीं जानते कि आबादी के जीवित रहने के लिए न्यूनतम सेवन कितना आवश्यक है, तो प्रतिदिन कैलोरी सेवन की मात्रा बहुत अधिक स्पष्ट नहीं होती है। इस सिद्धांत के अनुसार, एक अच्छे संकेतक को मापा जाना चाहिए, "प्रत्येक संकेतक के संख्यात्मक मूल्य के संदर्भ में मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि का एक न्यूनतम स्तर स्थापित किया जाना चाहिए।" यह गुण कि प्रत्येक संकेतक को मापा जाना चाहिए, बहुत वांछनीय है, लेकिन अक्सर बहुत व्यावहारिक नहीं होता है। कच्चे श्रम बल भागीदारी दर जैसे संकेतकों के महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर को स्थापित करना हमेशा संभव नहीं होता है। हालाँकि जो आवश्यक है वह यह है कि विश्लेषक चर की अनुदैर्ध्य या स्थानिक तुलना करके कुछ मानक कथन कर सकता है और उसे करना चाहिए। छठी बात, एडेई (1973) ने सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की एक और विशेषता को प्रतिबंधित या अप्रतिबंधित के रूप में पहचाना है। वह अप्रतिबंधित संकेतक को एक चर के रूप में परिभाषित करता है जो किसी भी संख्यात्मक मान को ग्रहण कर सकता है, और प्रतिबंधित संकेतक को एक चर के रूप में परिभाषित करता है जिसके अधिकतम मूल्य पर एक सीमा रखी जाती है। इस प्रकार साक्षरता दर जैसे प्रतिशत में व्यक्त किए जाने वाले चर को प्रतिबंधित चर माना जाएगा, जबकि प्रति व्यक्ति आय जैसे चर जो किसी भी मूल्य को ग्रहण कर सकते हैं उन्हें अप्रतिबंधित के रूप में वर्णित किया जाता है। वह अप्रतिबंधित संकेतकों के उपयोग की वकालत करता है, भले ही व्यवहार में, जैसा कि हमारे बाद के विश्लेषण में होता है, हम पाते हैं कि किसी को प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित दोनों संकेतकों का उपयोग करना पड़ता है। इसके अलावा, प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित दोनों संकेतकों के अपने फायदे और नुकसान हैं। अंत में, जैसा कि मोजर (1972) ने सुझाव दिया है कि सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों को विकास कार्यक्रमों के इनपुट के बजाय आउटपुट से संबंधित होना चाहिए। क्या कोई ऐसे संकेतक चुन पाएगा जो इसे और ऊपर निर्दिष्ट सभी अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं, यह डेटा की उपलब्धता पर निर्भर करता है। आगे हम विकास के स्तर को मापने और जिलों की रैंकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को सूचीबद्ध करते हैं।

सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों के विकल्प:

इस विचार से प्रेरित होकर कि कल्याण को मौद्रिक संकेतकों द्वारा पूरी तरह से नहीं पकड़ा जा सकता है, विकास का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला समग्र सूचकांक तीन चरों वाला भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक है: (1) शिशु जीवित रहने की दर, (2) वयस्क साक्षरता दर, और (3) जीवन प्रत्याशा, हालाँकि, यह आम तौर पर

माना जाता है कि सामाजिक-आर्थिक विकास को बड़ी संख्या में विशेषताओं के आधार पर मापा जाना चाहिए जो प्रासंगिक और व्यवहार्य हो। इसलिए, हम लोगों की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के विभिन्न समूहों से चरों को शामिल करके भौतिक जीवन गुणवत्ता माप के दायरे को व्यापक बनाने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक जिले को अपने लिए विशिष्ट परिस्थितिजन्य कारकों के साथ-साथ सभी जिलों के लिए समान प्रशासनिक और वित्तीय कारकों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक-आर्थिक विकास के स्तर का आकलन करने के लिए जिलों को अध्ययन में शामिल किया गया है।

कृषि क्षेत्र के विकासात्मक संकेतक :

1. बोया गया शुद्ध क्षेत्रफल का प्रतिशत 2. प्रति कृषक शुद्ध दर्शाया गया क्षेत्रफल 3. एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्रफल का प्रतिशत 4. गेहूं की उत्पादकता 5. चावल की उत्पादकता 6. दूध उत्पादन (लीटर/व्यक्ति/वर्ष) 7. फलों और सब्जियों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र 8. ट्रैक्टरों की संख्या (दिखाए गए शुद्ध क्षेत्रफल के प्रति 1,000 हेक्टेयर) 9. सिंचाई के लिए नलकूपों और पम्पिंग सेटों की संख्या (दर्शाए गए शुद्ध क्षेत्रफल के प्रति 1,000 हेक्टेयर) 10. शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 11. पशुधन की संख्या (प्रति 100 व्यक्ति) 12. मुर्गीपालन की संख्या (प्रति 1,000 व्यक्ति) 13. पशु चिकित्सा संस्थानों की संख्या (प्रति 10,000 पशुधन पर) 14. सहकारी समितियों की कृषकों की सदस्यता (प्रति 1,000 व्यक्ति) 15. विनियमित बाजारों की संख्या (प्रति लाख हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र) 16. राज्य के स्वामित्व वाले गोदामों की क्षमता (किलोग्राम/व्यक्ति) 17. वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्रफल 18. कृषि उत्पादन का सकल मूल्य (रु./हेक्टेयर) 19. अनाज उत्पादन (किग्रा/व्यक्ति) 20. कृषि सकल मूल्य संवर्धन (रु./व्यक्ति) 21. प्रयुक्त उर्वरक (किग्रा/हेक्टेयर) 22. पुरुषों में साक्षरता दर 23. महिला साक्षरता दर 24. अनुसूचित जाति जनसंख्या में साक्षरता दर 25. प्राथमिक विद्यालयों की संख्या (प्रति लाख व्यक्ति) 26. लिंग अनुपात (0-6 वर्ष के बच्चे) 27. जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी.) 28. जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर (2001-2011) 29. स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या (प्रति लाख व्यक्ति) 30. स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या (प्रति लाख व्यक्ति) 31. समस्याग्रस्त गांवों का प्रतिशत 32. शहरीकरण का प्रतिशत 33. डाकघरों की संख्या (प्रति लाख व्यक्ति) 34. वाहनों की संख्या (प्रति 1,000 व्यक्ति) 35. सड़कों की लंबाई (प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र में किमी में) 36. दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, होटलों और रेस्तरां की संख्या (प्रति लाख व्यक्ति) 37. दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, होटलों और रेस्तरां में काम करने वाले लोगों की संख्या (प्रति लाख व्यक्ति) 38. बैंकों की संख्या (प्रति लाख व्यक्ति) 39. पंजीकृत कारखानों की संख्या 40. पंजीकृत कारखानों की संख्या (प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र) 41. कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या (प्रति 10,000 व्यक्ति) 42. विनिर्माण उद्योग द्वारा प्रति व्यक्ति मूल्य संवर्धन (रु. में) 43. बिजली कनेक्शनों की संख्या (प्रति दस व्यक्ति)।

सांख्यिकीय विश्लेषण में कुल 43 विकासात्मक संकेतक शामिल किए गए हैं। ये संकेतक भले ही एक समग्र सूची न बनाते हों, लेकिन ये प्रत्येक जिले के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रमुख परस्पर क्रियाशील घटक हैं और इन्हें केवल डेटा उपलब्धता बाधाओं के आधार पर चुना जाता है। 43 में से इक्कीस संकेतक सीधे कृषि क्षेत्र में विकास से संबंधित हैं। पाँच संकेतक औद्योगिक क्षेत्र में विकास की प्रगति को दर्शाते हैं और शेष सत्रह संकेतक अवसंरचना सेवाओं में विकास के स्तर को प्रस्तुत करते हैं। कुछ संकेतक सहसंबद्ध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सिंचाई के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र और गेहूं की फसल की उत्पादकता सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हो

सकती है। हालाँकि, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास अनुसंधान संस्थान (UNRISD 1970) द्वारा तर्क दिया गया है कि अन्य विकास चर के साथ उच्च अंतर-सहसंबंध वाले चर कम सहसंबंध वाले चर से बेहतर हैं।

विश्लेषण:

जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है कि सामाजिक-आर्थिक विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है और इसका मूल्यांकन किसी एक संकेतक द्वारा पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, जब कई संकेतकों का अलग-अलग विश्लेषण किया जाता है, तो वे वास्तविकता की एकीकृत और आसानी से समझ में आने वाली तस्वीर पेश नहीं करते हैं। इसके लिए विभिन्न विकासात्मक संकेतकों के इष्टतम संयोजन के आधार पर सामाजिक-आर्थिक विकास के एक समग्र सूचकांक का निर्माण करना आवश्यक है। विभिन्न संकेतकों के प्रभाव को संयोजित करने के लिए कई विधियाँ (जैसे, प्रमुख घटक विश्लेषण, बहु-कारक विश्लेषण, एकत्रीकरण विधि, मौद्रिक सूचकांक, अनुपात सूचकांक और रैंकिंग विधि) हैं। हालाँकि इन विधियों की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनमें से अधिकांश विधियों की अपनी सीमाएँ हैं। जीवन की गुणवत्ता के विश्लेषण के कुछ सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले तरीकों की संक्षिप्त समीक्षा आवश्यक है।

प्रमुख घटक विश्लेषण:

सामाजिक-आर्थिक विकास के स्तर के मापन पर साहित्य के सर्वेक्षण से पता चलता है कि अधिकांश अध्ययनों में प्रमुख घटक विश्लेषण दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है। जैसा कि भाटिया और राय (2004) ने बताया है, यह विधि आम तौर पर विकासात्मक संकेतकों के बारे में प्रतिबंधात्मक मान्यताओं पर आधारित है, यानी, चर संकेतक रैखिक रूप से संबंधित हैं। जब गैर-रैखिकता मौजूद होती है, तो घटक विश्लेषण उचित नहीं होता है। चूंकि यह विधि भिन्नताओं को मापती है, इसलिए इसे चर के स्केलिंग द्वारा निर्धारित किया जाता है, और वास्तव में केवल तभी समझ में आता है जब चर तुलनीय पैमाने पर हों। इसके अलावा, कोई भी सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में रूपांतरित चर को कोई विशेष अर्थ नहीं दे सकता है। वे कृत्रिम ऑर्थोगोनल चर हैं जो किसी विशेष आर्थिक स्थिति के साथ सीधे पहचाने नहीं जा सकते हैं।

बहु कारक विश्लेषण:

यह विधि डेटा तालिका से संबंधित है जिसमें व्यक्तियों के एक समूह को चर के कई सेटों द्वारा वर्णित किया जाता है। इस विधि का मुख्य लाभ यह है कि 'कारक लोडिंग का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है
११विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के प्रभाव को संयोजित करने के लिए भार। यह विधि कुछ हद तक भार चुनने में मनमानी से बचती है। इस पद्धति की मुख्य सीमा यह है कि जब संकेतक माप के विभिन्न पैमाने पर प्रस्तुत किए जाते हैं, तो यह विकास के सार्थक और तुलनीय समग्र सूचकांक पर पहुंचने के उद्देश्य को पूरा नहीं करती है।

मौद्रिक सूचकांक:

इस पद्धति में सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक संकेतकों को मौद्रिक मूल्यों में परिवर्तित किया जाता है तथा इन मूल्यों के योग को विकास का समग्र सूचकांक माना जाता है। विकासात्मक संकेतकों के मौद्रिक मूल्य स्थान-स्थान तथा समय-समय पर बदल सकते हैं। इस प्रकार यह पद्धति समग्र सूचकांक पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस पद्धति में एक और कठिनाई यह भी आ सकती है कि सभी संकेतकों को मौद्रिक मूल्यों में परिवर्तित नहीं

किया जा सकता। शहरीकरण, जनसंख्या घनत्व, लिंग अनुपात, शिक्षा स्तर आदि जैसे संकेतकों को मौद्रिक मूल्यों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

एकत्रीकरण विधि:

यह विधि सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों के मूल्यों को जोड़कर विकास के समग्र सूचकांक के रूप में उपयोग करती है। यह उपयुक्त नहीं है क्योंकि इस विधि के उपयोग से प्राप्त समग्र विकास सूचकांक उस इकाई पर निर्भर करता है जिसमें डेटा रिकॉर्ड किया जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच अंतर-संबंध:

समावेशी विकास के लिए यह बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र एक साथ फल-फूलें। हरियाणा राज्य के लिए कृषि क्षेत्र, बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं, औद्योगिक विकास और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच पियर्सन द्विचर सहसंबंध गुणांक तालिका 7 में दिए गए हैं। कि राज्य में सामाजिक-आर्थिक विकास के स्तर को बढ़ाने में बुनियादी ढांचा सुविधाएं सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अनुमानित सहसंबंध गुणांक 0.78 है।

कृषि और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच सहसंबंध गुणांक पाँच प्रतिशत के स्तर पर सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया है। यह दर्शाता है कि समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास कृषि-संस्कृति क्षेत्र के विकास के साथ अत्यधिक जुड़ा हुआ है। वास्तव में, जो जिले कृषि की दृष्टि से उन्नत हैं, उनमें समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास का उच्च स्तर पाया जाता है। दूसरे शब्दों में, हरियाणा में कृषि और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास साथ-साथ चल रहे हैं।

औद्योगिक विकास और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच संबंध काफी कमजोर और महत्वहीन है। इसी तरह, राज्य में कृषि और औद्योगिक विकास सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए नहीं पाए गए हैं। ये परिणाम नारायण एट अल. (2003) द्वारा कर्नाटक (दक्षिण भारत में स्थित राज्य) के लिए किए गए निष्कर्ष के अनुरूप हैं।

भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास के स्तरों की अंतर-क्षेत्रीय तुलना':

प्रस्तुत परिणामों की जांच से पता चलता है कि समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के मामले में दक्षिण क्षेत्र, उत्तरी और मध्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर विकसित है, क्योंकि समग्र सूचकांक के इसके मूल्य काफी कम हैं। समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में, दक्षिण क्षेत्र के लिए समग्र सूचकांक का औसत मूल्य 0.717 है, जबकि उत्तर क्षेत्र के लिए यह 0.776 और मध्य क्षेत्र के लिए 0.853 है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि दक्षिणी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधाएं भी उत्तरी और मध्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर विकसित हैं। औद्योगिक विकास के समग्र सूचकांक के औसत मूल्य हैं: दक्षिण क्षेत्र के लिए 0.491, मध्य क्षेत्र के लिए 0.841 और उत्तर क्षेत्र के मामले में 0.705 है। हालांकि, उत्तरी और मध्य क्षेत्रों की तुलना में दक्षिणी क्षेत्र कृषि की दृष्टि से कम विकसित है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विकास के स्तरों में, विशेष रूप से एक ओर दक्षिण क्षेत्र और दूसरी ओर अन्य क्षेत्रों के बीच, बहुत असमानता है। उत्तरी क्षेत्र दूसरा सबसे विकसित क्षेत्र है। इसके अलावा, विकास का पैटर्न, विशेष रूप से औद्योगिक विकास के मामले में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में अपेक्षाकृत सममित है। मध्य क्षेत्र के मामले में, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के समग्र सूचकांक का औसत मूल्य काफी अधिक है, यानी निम्न

स्तर का विकास जो उच्च स्तर की विषमता के साथ है। यह निष्कर्ष उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में होने वाली निम्न-स्तरीय विषमता विकास प्रक्रियाओं की परिकल्पना का समर्थन करता है।

विकास के पैटर्न की एक अंतरराज्यीय तुलना से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक विकास की विषमता मध्यप्रदेश से बहुत कम है, इसके अलावा, उत्तर प्रदेश का सामाजिक-आर्थिक विकास का स्तर अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है, 177.5 कम विकसित जिलों के लिए आदर्श जिले और विकासात्मक संकेतकों के संभावित लक्ष्य के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह जांच करना है कि कम विकसित जिलों के विकास के स्तर में सुधार लाने के लिए विकासात्मक संकेतकों में किस हद तक सुधार की आवश्यकता है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए संसाधनों के कुशल आवंटन के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है। कम विकसित जिलों के लिए विकासात्मक संकेतकों के संभावित लक्ष्यों के आकलन के लिए, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के समग्र सूचकांक और विभिन्न जिलों के बीच विकासात्मक दूरी के आधार पर मॉडल जिलों की पहचान की जाती है। मॉडल जिलों के बीच विभिन्न संकेतकों का सर्वोत्तम मूल्य कम विकसित जिलों के संभावित लक्ष्य के रूप में लिया जाता है। मध्य क्षेत्र के कम विकसित जिलों के लिए मॉडल जिलों की पहचान की गई है । कम विकसित जिलों की तुलना में मॉडल जिले बेहतर विकसित हैं। दक्षिण क्षेत्र के कम विकसित जिलों के लिए मॉडल जिलों की पहचान कि गई है। यह देखा गया है कि अधिकांश कम विकसित जिलों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास में मॉडल जिले हैं। मॉडल जिलों के विकासात्मक संकेतकों के सर्वोत्तम मूल्यों को कम विकसित जिलों के लिए संभावित लक्ष्य के रूप में लिया जाएगा। विकासात्मक संकेतकों के वर्तमान मूल्य के साथ-साथ कम विकसित जिलों के लिए विभिन्न विकासात्मक संकेतकों में सुधार की आवश्यकता है।

कृषि, औद्योगिक, अवसंरचना और समग्र सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मूल्यांकन किया गया है। चयनित राज्य उत्तर प्रदेश के 06 जिलों को अध्ययन में शामिल किया गया है और समग्र सूचकांकों के मूल्यों के अनुसार चार विकास श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पिछड़े जिलों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक एजेंडा और अन्य नीतिगत उपाय जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में एक समान क्षेत्रीय विकास लाने के लिए किए जाने की आवश्यकता प्रदान किए गए हैं। निर्मित सामाजिक-आर्थिक विकास सूचकांक से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र मध्य और उत्तरी क्षेत्रों की तुलना में अत्यधिक और समान रूप से विकसित हुआ है। विकास के पैटर्न की एक अंतरराज्यीय तुलना से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक विकास की विषमता अन्य राज्यों से बहुत कम है। इसके अलावा, मध्यप्रदेश, झारखंड की तुलना में उत्तर प्रदेश का सामाजिक-आर्थिक विकास का स्तर बेहतर है।

परिणाम एवं निष्कर्ष:

परिणाम से पता चलता हैं कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के भीतर और उनके बीच विभिन्न जिलों में सामाजिक-आर्थिक विकास के स्तर में व्यापक असमानताएँ मौजूद हैं। बुनियादी ढाँचा सेवा क्षेत्र में विकास का स्तर समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ पाया गया है, जो दर्शाता है कि देश में इन क्षेत्रों की वृद्धि और प्रगति साथ-साथ चल रही है।

परिणाम से पता चलता हैं कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का स्तर कृषि और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता है, जबकि कृषि विकास समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। निम्न स्तर के विकसित क्षेत्रों में विषमता अधिक पाई जाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, औद्योगिक विकास का क्षेत्रीय पैटर्न राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पक्ष में अत्यधिक तिरछा पाया गया है। यह देखा गया है कि औद्योगिक विकास का राज्य में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। कम विकसित जिले कृषि और बुनियादी ढाँचे की सुविधाओं में भी खराब रूप से विकसित हैं।

एक समान क्षेत्रीय विकास लाने के लिए आदर्श जिलों की पहचान की गई है तथा अल्प विकसित जिलों के लिए विभिन्न विकास संकेतकों के लिए संभावित लक्ष्यों का आकलन किया गया है। अपेक्षाकृत कम विकसित जिलों में अधिक सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक तथा खेती की अन्य आधुनिक तकनीकें उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। अल्प विकसित जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सिंचाई तथा परिवहन जैसी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में सुधार लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा उन जिलों में सतत सामाजिक-आर्थिक विकास लाने के लिए एक पूर्व अपेक्षा है। ग्रामीण लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए पिछड़े जिलों में रोजगार के अवसर सृजित किए जाने चाहिए। समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा शहरीकरण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। हमारे अध्ययन से नीतिगत निहितार्थ स्पष्ट है। यदि सरकार विकास सुविधाओं का समान वितरण चाहती है तो उन जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जिनका विकास आदर्श जिलों से बहुत पीछे है। यह देखा गया है कि अल्प विकसित जिलों के सभी आयाम अल्प विकसित नहीं हैं, बल्कि कुछ आयाम उच्च या मध्यम स्तर के विकसित हैं। समतामूलक सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए ठोस क्षेत्र तथा आयाम विशिष्ट नीतिगत कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकारों और केंद्र की ओर से ठोस प्रयासों की आवश्यकता होगी। सरकार, सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग और आम लोगों की ओर से दृढ़ संकल्प और भी महत्वपूर्ण है। अध्ययन में वर्णित विश्लेषण अनिवार्य रूप से सीमित है। विभिन्न समय अवधियों में तुलना करने के लिए आगे काम करने की आवश्यकता है। इस तरह, विशेष जिलों या गांवों की प्रगति का अधिक सटीक आकलन करना संभव हो सकता है। जैसा कि एरीफ ने उल्लेख किया है कि इस तरह के तुलनात्मक अध्ययन मुख्य रूप से परिकल्पना परीक्षण के बजाय परिकल्पना उत्पन्न करने के उद्देश्यों की ओर निर्देशित होते हैं और क्षेत्रीय नियोजन के लिए एक अतिरिक्त उपकरण के रूप में सुझाए जाते हैं।

संदर्भ:

1.एडेई, एस. (1973). आर्थिक विकास का मापन: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिनिधित्व की भूमिका का मात्रात्मक विश्लेषण, अप्रकाशित एम.एससी., यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो ,

2.मजूमदार, ए., मजूमदार, के., और चक्रवर्ती, एस. (1995), अंतर- और अंतर-क्षेत्रीय असमानता के पैटर्न: एक सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण। ,

3.एरीफ एस. (1982). मलेशिया में क्षेत्रीय असमानताएँ. सामाजिक संकेतक अनुसंधान, 17(3), 259-267.

4.एटकिंसन, ए., और बोरगुइग्नन, एफ. (1982), आर्थिक स्थिति के बहु-आयामी वितरण की तुलना, आर्थिक अध्ययन की समीक्षा, 49(2), 183-201,

5.भाटिया, बी.के. और राय, एस.सी. (2004)। छोटे क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास का मूल्यांकन, परियोजना रिपोर्ट, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली,

6.चौधरी. यू.डी.आर. (1992). आर्थिक विकास और जीवन स्तर में अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्यीय भिन्नताएँ. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक,

7.दासगुप्ता, बी. (1971). जिलों का सामाजिक-आर्थिक वर्गीकरण: एक सांख्यिकीय दृष्टिकोण. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 6(33),

8.ड्रेवनोव्स्की, जे. (1972). सामाजिक संकेतक और कल्याण माप: कार्यप्रणाली पर टिप्पणियाँ. जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंट स्टडीज़, 8(3),

9.इवुसी, के. (1976). घाना में क्षेत्रीय विकास के स्तरों में असमानताएँ. सामाजिक संकेतक अनुसंधान, 3(1), 75-110.

10.भारत सरकार (2011ए), सहस्राब्दि विकास लक्ष्य भारत देश रिपोर्ट 2011, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली:

12.उत्तर प्रदेश सरकार (2012). आर्थिक सर्वेक्षण, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली: भारत सरकार,

13.गोस्टोव्स्की, जेड. (1970). अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के आधार पर लक्ष्य निर्धारण में वर्गीकरण उपायों का उपयोग. गुणवत्ता और मात्रा, 4(2),

14.हेलविग, जेड. (1967) टैक्सोनोमिक विधि के माध्यम से उच्च-स्तरीय मानव-शक्ति डेटा और देशों की टाइपोलॉजी के मूल्यांकन की प्रक्रिया (अप्रकाशित यूनेस्को कार्य पत्र),

15.कुरियन, एन. जे. (2000). भारत में क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ रही हैं: कुछ संकेतक. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 35(7),

16.कुरियन, एन. जे. (2007), आर्थिक और सामाजिक असमानताओं का बढ़ना: भारत के लिए निहितार्थ, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च,